राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियों और अवसरों पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

An Analytical Study on Challenges and Opportunities of NEP 2020

निर्देशक
डॉ. सिद्वेश्वर मिश्रा
शिक्षा संकाय
आई एस.बी.एम विश्वविघालय
छुरा गरियाबंद छ.ग.

शोधार्थी
पूर्णिमा कौशिक
शिक्षा संकाय
आई एस.बी.एम.विश्वविघालय
छुरा गरियाबंद छ.ग.

सारॉंश :

शिक्षा से आर्थिक और सामाजिक प्रगति होती है इसलिए प्रत्येक देश अपनी परंपरा के अनुसार अलग–अलग शिक्षा प्रणाली अपनाते हैं क्योंकि किसी भी देश के विकास के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक अच्छी तरह से सोची समझी और परिभाषित की गयी भविष्य की शिक्षा नीति की आवश्यकता होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020), जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, ये भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 पर नई शिक्षा नीति 2020 एक सुधार है । यह नीति व्यापक है इसमें प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो रुपरेखा बनाई गयी है उसमे उच्च शिक्षा के साथ–साथ भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रो में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए भी स्थान दिया गया है।

जैसा कि ऊपर ये बताया गया की NEP 2020, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर किया गया एक सुधार है जिसके लिए जनवरी 2015 में, पूर्व कैबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम के नेतृत्व में एक समिति गठित की गयी जिसने नई शिक्षा नीति के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरु किया इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर जून 2017 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन के नेतृत्व में एक पैनल द्वारा 2019 में एनईपी का मसौदा प्रस्तुत किया गया था नई शिक्षा नीति के इस मसौदे को लेकर पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर कई सार्वजनिक

परामर्श किये बाद में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक कठोर परामर्श प्रक्रिया के निष्कर्ष के आधार पर नई शिक्षा नीति को जारी किया गया।

नीति का उद्देश्य यह है की 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए भरसक प्रयास किया जाये साथ ही नीति जारी होने के फौरन बाद सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी को भी किसी भाषा विशेष का अध्ययन करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा साथ में ये भी कहा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

प्रस्तावना –

किसी भी देश की प्रगति के साथ–साथ उसके नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिये शिक्षा को सबसे महत्त्वपूर्ण आधार माना गया है। देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक आधुनिक भारत के निर्माण में भारतीय शिक्षा प्रणाली की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

आधुनिक समय की जरूरतों के अनुरूप भारतीय शिक्षा प्रणाली में अपेक्षित बदलाव लाने के लिये केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2020 में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' (National Education Policy 2020) को मंजूरी दी गई। 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020' के माध्यम से भारतीय शिक्षा परिदृश्य में बड़े बदलावों का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। हालाँकि इसकी सफलता प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से लेकर अन्य सभी हितधारकों द्वारा इसके कार्यान्वयन के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता पर निर्भर करेगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2030–2032 तक भारत दस ट्रिलियन डॉलर की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्थाएं भारत के प्राकृतिक संसाधनों से संचालित नहीं की जा सकती इनको संचालित करने के लिए ज्ञान के संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और इस आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए भारतीय शिक्षा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान सरकार ने राट्रीय शिक्षा नीति 2020 **शुरू** करने का निर्णय लिया है।

चौथे औद्योगिक क्रांति का लाभ उठाने के लिए प्रधानमंत्री के तत्कालिक आह्वान के अनुरूप भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत की गयी जो सभी

को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में तथा राष्ट्र की केंद्रित शिक्षा प्रणाली को एक समान और जीवंत ज्ञान में स्थायी रूप से बदलने में सीधे योगदान देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020) , जिसे 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था भारत की नई शिक्षा प्रणाली के दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। नई शिक्षा नीति 2020 ने पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, की जगह ले ली है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है और यह नीति 2020 भारत को बदलने में सीधे प्रकार से योगदान प्रदान करती है और भारतीय लोकाचार में निहित शिक्षा प्रणाली को देखती है । इसका उद्देश्यधर्म, लिंग, जाति या पंथ के किसी भी भेदभाव के बिना, सभी को बढ़ने और विकसित होने के लिए एक समान मंच प्रदान करना और सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके मौजूदा जीवंत ज्ञान समाज को बनाए रखना और उसकी देखभाल करना है। यह भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने की दिशा में भी एक कदम है। इस नीति में यह परिकल्पना की गई है कि हमारे संस्थानों के समान पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र को,छात्रों में मौलिक कर्तव्यों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करनी चाहिए और संवैधानिक मूल्यों, अपने देश और एक बदलती दुनिया के साथ एक संबंध पैदा करना चाहिए । इस नीति का दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच ज्ञान, कौशल, आत्मविश्वास, बुद्धि औरकर्म के साथ न केवल विचार बल्कि मूल्यों और दृष्टिकोणों में भी विकास करना है, जो मानव अधिकारों, सतत विकास और जीवन का समर्थन करते हैं और वैश्विक कल्याण के लिए एक जिम्मेदार प्रतिबद्धता, जिससे वास्तव में एक वैश्विक नागरिक प्रतिबिंबित होता है।
गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का उद्देश्य, ऐसे व्यक्तियों का विकास करना होना चाहिए जो उत्कृष्ट, विचारशील और अच्छी रचनात्मक प्रवत्ति के हों।
नई शिक्षा नीति 2020 पांच स्तंभों पर केंद्रित हैः वहनीयता, अभिगम्यता, गुणवत्ता, न्यायपरस्ता और जवाबदेही – निरंतर सीखने की प्रकिर्या को सुनिश्चित करने के लिए।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालना है तथा नई शिक्षा नीति 2020 से संबंधित प्राथमिक और माध्यमिक डेटा का विश्लेषण करना है। इसके अन्य मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं।

- नई शिक्षा नीति 2020 को पेश करना।
- नई शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा की मुख्य विशेषताओं को देखना।
- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि को दर्शाने लिए।
- शिक्षा पर राज्य के खर्च को सकल घरेलू उत्पाद के 4 से बढ़ाकर 6 करने की एक झलक देने के लिए।

अनुसंधान क्रियाविधि

यह अध्ययन पाठ्य, आलोचनात्मक, मूल्यांकनात्मक, वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक विधियों का उपयोग करते हुए प्राथमिक और माध्यमिक स्रोतों के माध्यम से उच्च शिक्षा के विशेष संदर्भ के साथ एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में नई शिक्षा नीति 2020 के संपूर्ण अध्ययन पर भी ध्यान केंद्रित करता है।

डेटा संग्रह

शोध अध्ययन के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों से आँकड़ों का संकलन किया गया है जिसके आधार पर सम्पूर्ण प्रपत्र का विश्लेषण किया गया है।

प्राथमिक स्रोत

प्राथमिक संसाधन नई शिक्षा नीति 2020 के मूल पाठ से एकत्र किए गए हैं जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।

माध्यमिक स्रोत

एक माध्यमिक संसाधन एक स्रोत है जो नई शिक्षा नीति 2020 पर संदर्भ पुस्तकों सहित पुरानी या गैर–मूल जानकारी प्रदान करता है। माध्यमिक स्रोतों में जीवनी, लेखक के कार्यों के महत्वपूर्ण अध्ययन, शोध पत्र और शोध प्रबंध, शोध पुस्तकें, व्यक्तिगत साक्षात्कार, विकिपीडिया, ब्रिटानिका और अन्य वेबसाइटें शामिल हैं।

अध्ययन का महत्व

वास्तविक तथ्यों पर आधारित इस अध्ययन के निष्कर्ष समाज के हित में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस अध्ययन क्षेत्र में पूर्व अनुसंधान की कमी के कारण यह शोध मॉडल इस अध्ययन के लिए प्रस्तावित है। शोधकर्ता इस वर्तमान अध्ययन के सभी पहलुओं को समझाने का प्रयास करेगा। वर्तमान शोध नई शिक्षा नीति 2020 के नियम एवं शर्तों के अनुसार उच्च शिक्षा के सुधारों को समझने में मदद करेगा। यह शोध नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में पाठकों के बीच जागरूकता पैदा करने का प्रयास करेगा।

साहित्य की समीक्षा

संक्षेप में, इसमें पिछले अध्ययनों की समीक्षा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है, जो इस अध्ययन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रासंगिक है। इसमें नई शिक्षा नीति 2020 और विशेष रूप से उच्च शिक्षा से संबंधित अध्ययनों पर किए गए कार्यों की एक झलक देखने को मिलती है।

पीएस ऐथल और शुभ्रज्योत्सना ऐथल के अनुसार उनके शोध पत्र ''भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का विश्लेषण इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में।'' "भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधार के लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के लिए और साथ ही बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। हर उच्च शिक्षा संस्थान में गुणवत्ता फ्री–शिप्स और स्कॉलरशिप के साथ योग्यता–आधारित प्रवेश को प्रोत्साहित करके, संकाय सदस्यों के रूप में योग्यता और अनुसंधान आधारित निरंतर प्रदर्शन, और निकायों को विनियमित करने में योग्यता आधारित सिद्ध नेताओं, और प्रौद्योगिकी–आधारित के माध्यम से प्रगति की स्व–घोषणा के आधार पर द्विवार्षिक मान्यता के माध्यम से गुणवत्ता की सख्त निगरानी, एनईपी–2020 के 2030 तक अपने उद्देश्यों को पूरा करने की उम्मीद है ।

अजय कुरियन और सुदीप बी चंद्रमना के शब्दों में, "नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा पूरी तरह से कई लोगों द्वारा अप्रत्याशित थी। नई शिक्षा नीति 2020 ने जिन बदलावों की सिफारिश की है, वे कुछ ऐसे थे जिन्हें कई शिक्षाविदों ने कभी आते नहीं देखा। यद्यपि शिक्षा

नीति ने स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को समान रूप से प्रभावित किया है, यह लेख मुख्य रूप से नई शिक्षा नीति 2020 और उच्च शिक्षा पर इसके प्रभाव पर केंद्रित है। यह पत्र नई शिक्षा नीति की मुख्य विशेषताओं को भी रेखांकित करता है और विश्लेषण करता है कि वे मौजूदा शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित करते है ।

नई शिक्षा नीति में रीयल–टाइम मूल्यांकन प्रणाली और परामर्शी निगरानी और समीक्षा ढांचे के लिए आश्वस्त रूप से प्रावधान किया गया है। यह शिक्षा प्रणाली को पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए हर दशक में एक नई शिक्षा नीति की अपेक्षा करने के बजाय, अपने आप में लगातार सुधार करने के लिए सशक्त बनाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : उच्च शिक्षा में सुधार

यह नीति ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण में परिवर्तनकाल के लिए एक व्यापक ढांचा है। इस नीति का उद्देश्य 2021 तक भारत की शिक्षा प्रणाली को बदलना है। नई शिक्षा नीति को स्कूल स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक प्रणाली में औपचारिक परिवर्तनों को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से पेश किया गया है। बदलते परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, अब से शैक्षिक सामग्री प्रमुख अवधारणाओं, विचारों, अनुप्रयोगों और समस्या समाधान के कोणों पर ध्यान केंद्रित करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति से देश की उच्च शिक्षा प्रणाली पर सकारात्मक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। यह तथ्य कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की अनुमति है, सरकार की एक सराहनीय पहल है। इससे छात्रों को अपने देश में शिक्षा की समग्र गुणवत्ता का अनुभव करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) को मौजूदा 26 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने के लिए एनईपी 2020 की कल्पना की गई थी। इसका उद्देश्य मुक्त और दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करके छात्रों के समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करना है।

इसके अलावा, देश में अनुसंधान कार्य को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना की जाएगी। देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए

एकल नियामक के रूप में परिकल्पित एक राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी) की स्थापना की जाएगी। भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (एचईसीआई) में विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने के लिए कई कार्यक्षेत्र होंगे। सभी सरकारी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी और समान स्तर की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए एक सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) स्थापित करने के प्रयास किए जाएंगे।

साइबर सुरक्षा में शिक्षा और कौशल

विश्व आर्थिक मंच 2021 की वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 के अनुसार, 'साइबर सुरक्षा विफलता' दुनिया के लिए चौथा सबसे महत्वपूर्ण खतरा है। जैसा कि चल रही महामारी के कारण शिक्षा और अध्यन पहले ही साइबर स्पेस में चली गई है, प्रत्येक व्यक्ति की गोपनीयता और सुरक्षा की रक्षा करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इस प्रकार, चूंकि डिजिटलीकरण को अपनाना केंद्र स्तर पर है, इसलिए हमारे नेटवर्क और साइबरस्पेस को सुरक्षित बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस वर्तमान परिदृश्य में, यह प्रासंगिक हो जाता है कि 'साइबर सुरक्षा लचीलापन' के लिए क्षमता निर्माण को प्रमुख महत्व दिया जाता है और सीखने की धारा के बावजूद उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है।

उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवाचार

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख क्षेत्रों में से एक सरकारी और निजी क्षेत्रों से उच्च अनुसंधान एवं विकास निवेश को प्रोत्साहित करना है। इससे इनोवेशन और इनोवेटिव माइंडसेट को बढ़ावा मिलेगा। इसे सुगम बनाने के लिए उद्योग आधारित कौशलध्अपस्किलिंगध्रीस्किलिंग के लिए एक मजबूत उद्योग प्रतिबद्धता और शिक्षा जगत के साथ घनिष्ठ हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा, ''बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)'' के बारे में ज्ञान बढ़ाने और इससे लाभ प्रदान करने के लिए इसके संरक्षण के लिए कौशल को विकसित करना प्रासंगिक हो जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ)

नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्थापित किए जाने के लिए परिकल्पित एनईटीएफ सही दिशा में एक कदम है। शिक्षण–शिक्षण वितरण के सभी आयामों में गुणवत्ता वाले एड–टेक उपकरण शैक्षणिक संस्थानों को जल्दी से अनुकूलित करने में मदद करेंगे। साइबर सुरक्षा

मानकों का पालन करने, फायरवॉल को अपनाने और घुसपैठ का पता लगाने वाले सिस्टम (आईडीएस) के अलावा 'गोपनीयता और सुरक्षा' सुनिश्चित करने के लिए अंतर्निहित साइबर सुरक्षा लचीलेपन के साथ ''ओपन–सोर्स डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म'' पर स्वदेशी एड–टेक टूल को होस्ट करने की आवश्यकता है। यह प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत गोपनीयता की रक्षा करेगा।

नयी शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख मुद्दे कुछ इस प्रकार से है

1. विभिन्न विषयों में छात्रों की प्रारंभिक स्ट्रीमिंग।
2. सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्रों के छात्रों का उच्च शिक्षा तक पहुंच पाने का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान सकल नामांकन अनुपात केवल 25ः से 30ः के मध्य ही रहा।
3. छात्रों को आकर्षित करने के लिए उच्च शिक्षा में नवाचार की कमी।
4. नवाचार करने के लिए पर्याप्त शिक्षक का न होना साथ ही और संस्थागत स्वायत्तता की कमी होना ।
5. अधिकांश विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचारों की कमी।
6. उच्च शिक्षा संस्थानों में शासन और नेतृत्व का उप–स्तर।
7. उत्कृष्ट एवं नवाचार स्थापित करने वाली संस्थानों को बाधित करते हुए नकली कॉलेजों को पनपने की अनुमति देने वाली एक भ्रष्ट नियामक प्रणाली।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कुछ अन्य उद्देश्य निम्न प्रकार से है

1. नई स्वीकृत उच्च शिक्षा प्रणाली (एनईपी 2020) की नीतियों पर प्रकाश डालना और उनका अवलोकन करना।
2. भारत में वर्तमान में अपनाई गई नीति के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की तुलना करना।
3. नई राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 में नवाचारों की पहचान करना।
4. भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली पर एनईपी 2020 के प्रभाव की भविष्यवाणी करना।
5. एनईपी 2020 की उच्च शिक्षा नीतियों के गुणों पर चर्चा करना।
6. अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए एनईपी 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और सुधार के लिए सुझाव।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में चुनौतियाँः

1. NEP 2020 के तहत वर्ष 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। गौरतलब है कि वर्तमान में देश में लगभग 1000 विश्वविद्यालय है ऐसे में इतने अधिक छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये बहुत से नए विश्वविद्यालयों की स्थापना करनी होगी।जो नीति के घोषित लक्ष्यों में से एक है, इसका मतलब यह होगा कि हमें अगले 15 साल के लिए हर हफ्ते एक नया विश्वविद्यालय खोलना होगा हर हफ्ते एक विश्वविद्यालय को निरंतर आधार पर खोलना निस्संदेह एक बड़ी चुनौती है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य 2 करोड़ बच्चों को स्कूल प्रणाली में वापस लाना है जो वर्तमान में स्कूलों में नहीं हैं। 15 वर्षों में इसे पूरा करने के लिए हर हफ्ते लगभग 50 स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता है।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के हस्तक्षेपों की आवश्यकता होगी, जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय तथा सहयोग, नए कानूनों का निर्माण या मौजूदा कानूनों मे संशोधन सहित अन्य विधायी हस्तक्षेप, वित्तीय संसाधनों की वृद्धि और नियामकीय सुधार आदि शामिल हैं।

4. इस नीति में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक पाठ्यक्रम, अवसंरचना, शिक्षण प्रणाली आदि में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव किया गया है, हालाँकि इन बदलावों को लागू करने के लिये संसाधनों (धन, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति आदि) का प्रबंध एक बड़ी चुनौती होगी।

5. वर्तमान में शिक्षा तंत्र और अन्य संसाधनों के मामले में देश के अलग–अलग राज्यों की स्थिति में भारी अंतर है, गौरतलब है कि वर्ष 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक (School Education Quality Index) में देश भर में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में भारी अंतर पाया गया है, ऐसे में छात्रों के लिये इन परिवर्तनों के अनुरूप स्वयं को ढालना कठिन होगा।

निष्कर्ष :

हर देश में अर्थव्यवस्था, सामाजिक स्थिति, प्रौद्योगिकी अपनाने और स्वस्थ मानव व्यवहार को तय करने में उच्च शिक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। उच्च शिक्षा के प्रसाद में देश के प्रत्येक नागरिक को शामिल करने के लिए जीईआर में सुधार देश की सरकार के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गुणवत्ता, आकर्षण, सामर्थ्य में सुधारकरनेके लिए नवीन नीतियां बनाकर और निजी क्षेत्र के लिए उच्च शिक्षा को खोलकर आपूर्ति बढ़ाने के साथ साथ हर उच्च शिक्षा संस्थान मे गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त नियंत्रण के साथ इस तरह के उददेश्य को प्राप्त करने की दिशा मे आगे बढ़ रही है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pd
2. https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Policy_2020
3. **Puri, Natasha (30 August 2019). A Review of the National Education Policy of the Government of India - The Need for Data and Dynamism in the 21st Century. SSRN.**
4. **Vedhathiri, Thanikachalam (January 2020), "Critical Assessment of Draft Indian National Education Policy 2019 with Respect to National Institutes of Technical Teachers Training and Research", Journal of Engineering Education, 33**
5. **Kumar, K. (2005). Quality of Education at the Beginning of the 21st Century: Lessons from India.Indian Educational Review 2. Draft National Education Policy 2019,**
6. **https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf 3. National Education Policy 2020.**
7. **https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/ NEP_Final_English.pdf referred on 10/08/2020**
8. https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/nep/NEP_Final_English.pdf
9. https://innovate.mygov.in/wpcontent/uploads/2019/06/mygov15596510111.pdf